अखिल भारतीय जन- विज्ञान नेटवर्क की ओर से जारी प्रारूप कथन

'फ्राइडेज फॉर फ्यूचर' जलवायु कार्रवाई: 23 सितंबर 2022

स्वीडन की युवा कार्यकर्ता ग्रेटा थम्बर्ग द्वारा 2018 में शुरू किए गए अभियान की निरंतरता में तथाकथित 'जलवायु हड़ताल' के कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी ,युवा व अन्य सहयोगी आंदोलन पूरे विश्व में भावी शुक्रवार आंदोलन के रूप में भाग ले रहे हैं ।इस वर्ष यह तिथि 23 सितंबर 2022 चुनी गई है ।अखिल भारतीय जन- विज्ञान नेटवर्क देशभर में अन्य देशों के जलवायु आंदोलनकर्ताओं के साथ मिलकर गतिविधियां कर रहा है ।इस बार की जलवायु हड़ताल का विशेष महत्व है। क्योंकि शायद गत वर्षो की तुलना में इसके दुष्प्रभाव ज्यादा विश्वव्यापी हैं जो हमारे मुंह पर एक तमाचा है ।यह इस बात का एहसास कराता है कि इसकी अनदेखी करने के क्या भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्बनिक ईंधन के भारी प्रयोग पर निर्भरता व अन्य चलताऊ आर्थिक गतिविधियां भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रही हैं।विकसित देश अधिकतर ऐसा कर रहे हैं जो लगभग 70% से ज्यादा उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार हैं। इसके काफी वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद हैं। विशेषकर छठी अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट ऐसा कहती है। पिछले 2 वर्षों में जारी तीन विशेष रिपोर्ट कह रही है कि वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है ।यह औद्योगिक क्रांति के समय से 1.2 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो गया है। इसके दुष्परिणाम जैसा पहले सोच रहे थे उससे कहीं अधिक हैं। यदि आज इस उत्सर्जन को रोक भी दिया जाए जैसा की 2015 के पेरिस सम्मेलन में सहमति बनी थी और 2021 के ग्लासगो सम्मेलन में अद्यतन की गई थी तो भी आज विश्व का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा चुका है। 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को तो छोड़िए ।प्रायद्वीपों पर रहने वाले ,अविकसित व विकासशील देशों में रहने वाले लोगों का भविष्य धुंधला व अनिश्चित है।

विकसित देशों समेत बहुत से देश पिछले वर्ष इसके परिणाम भुगत चुके हैं और इस वर्ष भी भुगत रहे हैं ।उत्तरी यूरोपियन देशों जैसे जर्मनी ,बेल्जियम से लेकर बाल्कन और इटली तक फैले देशों में कहीं कम वर्षा है तो कहीं बहुत अधिक वर्षा से बाढ़ के हालात हुए हैं ।यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इससे भारी जन -धन की हानि हो रही है ।गर्म लूऐं चल रही है जिससे पिछले दो वर्षों में जंगलों में आग लग रही है। स्पेन ,पुर्तगाल व इटली में भयंकर सूखा है ।गर्मी के कारण अमेरिका यहां तक कि कनाडा के जंगलों में भी आग लग रही है। वहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू चुका है। सूखे के कारण दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में पानी का भयंकर संकट है।

हम पड़ोसी पाकिस्तान में बाढ़ के दुष्परिणाम देख चुके हैं। इसे सुपर मानसून कहें या स्टेरॉयड मानसून जहां सामान्य से 3 से 5 गुना ज्यादा वर्षा हो रही हो। कहीं गर्मी से

ग्लेशियर पिघल रहे हैं ।लगभग 33 मिलियन लोग विस्थापित हो चुके हैं ।
भारत भी पिछले कुछ वर्षों सेअनअपेक्षित मानसून देख रहा है ।कहीं ज्यादा वर्षा है और केरल में बाढ़ है ।गोदावरी व ब्रह्मपुत्र बुरी तरह प्रभावित हैं ।एक ही दिन में 300 मिली मीटर से ज्यादा वर्षा या यूं कहें कि कुछ ही दिनों में पूरे महीने की वर्षा का कोटा सब कुछ तहस-नहस कर रहा है। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु व अन्य शहर बेनकाब हो चुके हैं क्योंकि वहां निकासी के प्रबंध ठीक नहीं ।
हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में भारी वर्षा ने बाढ़ व भूस्खलन से तबाही मचाई है। छोटे बांधों व जल संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है। इन सब के पीछे योजनाओं का अभाव तो है ही। क्षमता से ज्यादा शहरीकरण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बढ़ा देता है। तटीय प्रदेशों में भू क्षरण हो रहा है जिससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ रही है ।इससे व्यवसायी प्रोजेक्ट व दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो रहे हैं। दुर्भाग्य से तटीय क्षेत्र अधिनियमों को कमजोर किया जा रहा है।
ताजा आंकड़े कह रहे हैं कि मुंबई, कोच्चि ,चेन्नई विशाखापट्टनम ,पूरी, कोलकाता जैसे तटीय प्रदेश समुद्री जलस्तर के बढ़ने के दुष्परिणामों का शिकार हैं। ज्वार -भाटा व तूफानों के संकट हैं। सुंदरबन व पश्चिमी बंगाल के तटों पर जल चढ़ाव के कारण लोगों को रहने व रोजमर्रा के जीवन पर संकटा आ रहा है।
इस वर्ष की जलवायु हड़ताल के इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय जन -विज्ञान नेटवर्क व इससे जुड़ी अन्य संस्थाएं इन खतरों को आगाह करते हुए रैली व मांग करेंगे कि राज्य सरकारें इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर इस बारे में वायदे किए हैं कि वह जलवायु परिवर्तन के लिए किए जाने वाले वैश्विक प्रयासों का हिस्सा बनेगा। लेकिन सरकार ने देश में इसके प्रभावों के अनुरूप प्रतिरोधी कदम नहीं उठाए हैं ।जाहिर है कि यह सब करने की जरूरत है। लेकिन यहां केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय व मानवीय संसाधनों का संतुलन नहीं है। इसे देखते हुए तुरंत कोई राष्ट्रीय योजना बनाई जाए जो उनका प्रतिरोध कर सके जिसमें राज्य सरकारें ,विज्ञान व तकनीकी संस्थानों व अन्य नागरिक संगठनों की पूरी तरह भागीदार बने।